क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 329, शनिवार, 29 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

सज्जन कुमार 31 को कर सकते हैं अदालत में समर्पण

नई दिल्ली। सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार 31 दिसंबर को अदालत में समर्पण कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह समय सीमा बढ़ाने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर अपील पर शीतकालीन अवकाश के दौरान 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है। उच्चतम न्यायालय एक जनवरी तक बंद है और दो जनवरी से वहां सामान्य कामकाज शुरू होगा। उन्होंने कहा, हम उच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करेंगे। उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगों से संबंधित एक मामले में 17 दिसंबर को 73 वर्षीय पूर्व सांसद सज्जन कुमार को शेष सामान्य जीवन के लिये उम्र कैद और पांच अन्य दोषियों को अलग अलग अवधि की सजा सुनायी थी और उन्हें 31 दिसंबर तक समर्पण करने का आदेश दिया था।

बच्चों के साथ जघन्य यौन अपराध करनेवालों को मृत्युदंड की सजा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

हिटी,नई दिल्ली। बच्चों के साथ लगातार हो रहे जघन्य अपराध को रोकने की दिशा में केन्द्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए उसकी सजा को और कड़ी करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बच्चों के साथ जघन्य यौन अपराध करनेवाले दरिंदों के खिलाफ सजा को और कड़ी करते हुए उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा- प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें बच्चों के साथ जघन्य यौन अपराध को मौत की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किया गया ताकि प्राकृतिक आपदा या तबाही की स्थिति में बच्चों का शोषण न हो पाए या फिर गलत नीयत से समय पूर्व उसे बालिग बनाने के लिए उसके हार्मन्स में बदलाव जैसे कृत्य को रोका जा सके। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को खत्म करने के लिए उसके मैटिरियल को डिलिट नहीं करने या हटाने काफी जुर्माने को संशोधन में मंजूरी दी गई है।

योगी सरकार ने पार्टी ऑफिस के लिए अपना दल को बंगला देने से किया इनकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना दल (एस) की पार्टी ऑफिस के लिए बंगला आवंटित किए जाने की मांग को ठुकरा दिया है।

अपना दल पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहा है। अब बुधवार को योगी सरकार के इस फैसले के बाद दोनों दलों में तल्खी और बढ़ सकती है। एस्टेट ऑफिसर योगेश शुक्ला ने कहा, 'अपना दल (एस) पंजीकृत पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं।

नियमों के मुताबिक पार्टी ऑफिस के लिए सरकारी बिल्डिंग केवल मान्यता प्राप्त पार्टी को ही आवंटित की जा सकती है।' नवंबर माह में योगी सरकार ने माल अवेन्यू में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का बंगला आवंटित किया था। एस्टेट डिपार्टमेंट ने पटेल से कहा था कि वह पार्टी के कामकाज भी इसी बंगले में मैनेज करें। लेकिन पटेल ने कहा था कि उन्हें यह बंगला रहने के लिए चाहिए। उन्हें पार्टी ऑफिस के लिए अलग बंगला चाहिए। बीजेपी की सहयोगी अपना दल (एस) के नौ विधायक हैं और दो सांसद...।

अपना दल के कोटे से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में एक ही राज्यमंत्री हैं, जय कुमार सिंह 'जैकी'।

अंटार्कटिका में चार चीनी अनुसंधान स्टेशनों में से एक स्टेशन ताईशन स्टेशन की बिल्डिंग के सामने बुधवार को सामूहिक तस्वीर खिंचवाते चीनी अनुसंधानकर्ताओं का खोजी दल।

पढ़े-लिखे नौजवानों का आतंकी संगठन ऐसे कर रहा ब्रेनवॉश, बिछा रहा है अपना जाल

नई दिल्ली। कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के निशाने पर देश की राजधानी है। इसके लिए आईएस दिल्ली-एनसीआर में तेजी से अपनी जड़े जमाने में जुटा है।

आतंक का सबसे बड़ा आका और आईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी बेशक पिछले करीब साल-डेढ़ साल से लापता और खामोश है, लेकिन आतंक का जो बीज उसने बोया है, उससे अब उसके गुर्गे अब देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं।

हाल फिलहाल में देश की तमाम बड़ी एजेंसियों जैसे एनआईए और स्पेशल सेल की टीमों की कार्रवाई से तो यह पूरी तरह से साफ हो गया है।

अपने गहने बेचकर मॉड्यूल की की थी आर्थिक मदद

आतंकी मॉड्यूल के वित्तपोषण को लेकर महिला जांच के घेरे में

लखनऊ एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का दावा है कि 45 साल की एक महिला आतंकवादी मॉड्यूल के वित्तपोषण में शामिल रही है। एनआईए ने बुधवार को कई जगहों पर छापेमारी कर इस साजिश का भंडाफोड़ किया। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्तब्ध करने वाली इस घटना में एनआईए को राज्य की राजधानी में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के इशारे पर आतंकी साजिश में मां-बेटे दोनों के शामिल होने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य एनआईए द्वारा अमरोहा व लखनऊ सहित कई स्थानों पर बुधवार को की गई छापेमारी के दौरान पाए गए। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि नए आईएस माड्यूल ''हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम' के हिस्से के तौर पर लखनऊ सिटी स्टेशन के पास रह रही एक मुस्लिम महिला ने आतंकी साजिश को प्रायोजित करने के लिए अपने 2.75 लाख मूल्य के गहने बेच दिए थे। इस साजिश में महिला का बेटा भी शामिल था। सूत्रों ने कहा, महिला सोशल ''मीडिया पर बहुत सक्रिय' थी और वह आतंकवादी समूह के साथ संपर्क में एक सोशल मीडिया नेटवर्क साइट के जरिए आई। महिला द्वारा मुहैया कराए गए धन से आतंकवादी समूह ने कुछ हथियार व विस्फोटक खरीदे।

कहा, ऐसे लोग अब कृषि कर्ज माफ करने के नाम पर किसानों को मूर्ख बना रहे हैं

लूटने वाले अब ''चौकीदार' से डर रहे हैं : मोदी

धर्मशाला एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जिनकी धन लूटने की आदत थी, अब वे देश के ''चौकीदार' से डरे हुए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा, जिनकी लूटने की आदत रही है, वे अब देश के चौकीदार से डर रहे हैं और अब उसे गालियां दे रहे हैं।

मोदी ने कहा कि वे अब कृषि कर्ज माफ करने के नाम पर किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा के राज्य में शासन की पहली वर्षगांठ के मौके पर जनता को करीब घंटे भर के अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि उनकी केंद्र की सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन योजना के तहत चार किस्तों में 12,000 करोड़ रुपये सैनिकों को दिए हैं।

बीते 40 सालों से देश के सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन योजना की मांग थी। तत्कालीन सरकार ने हमारे सैनिकों को मूर्ख बनाया और इसके लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपये रखे। जब हम सत्ता में आए तो मैंने फाइल मंगाई तो अधिकारी अवाक रह गए। हमें महसूस हुआ कि इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।

सरकार के लिए एक बार में 12,000 करोड़ रुपये देना मुश्किल था, इसलिए हमने सैनिकों को बुलाया और

उनसे इसे चार से पांच किस्तों में देने के बारे में कहा और उन्होंने सहमति जताई। आज मैं खुश हूं कि हमने इसे चार किस्तों में दिया।

हिमालयी राज्य में पर्यटन व बागवानी को बढ़ावा देने का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,मैंने पेप्सी, कोला, फैंटा व दूसरे प्रकार के पेयों से जुड़े लोगों से मुलाकात की और इन पेयों में पांच फीसद प्राकृतिक फलों के रस को शामिल करने को कहा। बहुत सी कंपनियां ऐसा करने के लिए आगे आ रही हैं। आने वाले दिनों में हमारे किसानों के लिए यह एक अच्छा बाजार बनने जा रहा है।

केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील सरकार द्वारा दिए वित्तीय प्रोत्साहन की मौजूदा सरकार से तुलना करते हुए मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में हिमाचल प्रदेश को 21,000 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे।

जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो मुझे आप सभी की सेवा का अवसर मिला और हिमाचल को 71,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसी लिए संभव हुआ है कि भारत सरकार का मानना है कि इस राशि का हर पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए विवेकपूर्ण रूप से खर्च होगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सरकार के एक साल पूरे होने पर बधाई देते हुए मोदी ने कहा,हिमाचल प्रदेश मेरे घर जैसा है।

मैंने यहां कई सालों तक पार्टी के संगठन के लिए कार्य किया है। मोदी की रैली में आने के दौरान कांगड़ा जिले में बस के फिसल जाने से 40 छात्रों सहित 43 लोगों के घायल होने का जिक्र करते हुए मोदी ने राज्य सरकार से घायलों के लिए राहत के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि रैली से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में एहतियात बरतें।

स्कूल में सजा के तौर पर छात्रों के साथ घिनौना बर्ताव, कर दिया नग्न

एजेंसी ,तिरुपति। पुंगनूर स्थित एक निजी स्कूल में गृह कार्य पूरा नहीं करने पर सजा के तौर पर तीन छात्रों को नग्न अवस्था में कक्षा के बाहर खड़ा करने का मामला सामने आया है।

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए है।

वीडियो में कथित तौर पर तीसरी कक्षा के छात्र अपने हाथ ऊपर करके नग्न अवस्था में धूप में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस घटना की जांच के आदेश देते हुए चित्तूर जिले के कलेक्टर पीएस प्रद्युम्न ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एक शिक्षिका ने अपना गृह कार्य नहीं करने के लिए गुरुवार को बच्चों को कथित रूप से यह सजा दी थी। उन्होंने कहा कि दोष साबित होने पर स्कूल को दी गई सरकारी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पुलिस ने बताया कि छात्रों के अभिभावकों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

कांस्टेबल की सक्रियता ने लूटने से बचा ली कैश वैन

बेलीपार। शाबाश अखिलेश शाबाश। सक्रियता,चुस्ती-फुर्ती और पैनी नजर का इस्तेमाल किया और कैश वैन लुटने से बचा ली।

थोड़ी सी भी शिथिलता दिखाई होती तो कैश वैन लूट जाता और खाकी पर सवाल खड़ा हो जात। आम अवाम से लेकर हर अफसर की जुबां पर होता...पुलिस खड़ी रही और लुटेरों ने लूट ली कैश वैन।

नौसढ़ पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल अखिलेश सिंह को शुक्रवार की दोपहर एकला बाजार में हर कोई शाबाशी दे रहा था। अखिलेश ने काम ही ऐसा किया था।

बेलीपार क्षेत्र के एकला बाजार में स्थित पीएनबी की शाखा पर शुक्रवार की सुबह कैश वैन से दो कर्मचारी रुपये लेकर पहुंचे थे। उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड भी था। वैन के दो कर्मचारी रुपयों से भरा बाक्स निकालकर बैंक में पहुंचाने चले गए। गार्ड वहीं खड़ा था। इसी बीच एक बाइक से तीन युवक पहुंचे। तीनों ने हेलमेट लगा रखा था।

एक युवक नीचे उतरा और कैश वैन के सुरक्षागार्ड से जाकर उसे बातों में उलझा लिया।

दो अन्य युवक बाइक लेकर कैश वैन के पास पहुंचे। वे उसमें रखे रुपये निकालने के लिए बढ़े तभी बैंक की सुरक्षा व्यवस्था देखते वहां पहुंचे अखिलेश की बाइक सवारों पर नजर पड़ गई। वह शोर मचाते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े।

बाइक सवारों ने आवाज लगाई और कैशवैन के गार्ड से बात कर रहा युवक भी कूदकर उनकी बाइक पर बैठ गया। तीनों बाइक सवार महावीर छपरा की तरफ फरार हो गए।

अखिलेश ने चौकी इंचार्ज को दी सूचना

नौसढ़ चौकी इंचार्ज थोड़ी दूरी पर खड़े थे। अखिलेश ने उन्हें घटना के बारे में बताई।

चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्र और अन्य कांस्टेबलों ने कुछ दूर तक देखा भी लेकिन तब तक बाइक सवार आंखों से ओझल हो चुके थे।

बैंक और दुकानदार लगवाएं सीसी कैमरे

बेलीपार थानेदार अनिल कुमार सिंह ने बैंक की शाखाओं और बाजारों में प्रमुख दुकानों पर सीसी कैमरे लगवाने की गुजारिश की। उन्होंने कहा है कि सीसी कैमरे से दुकानदारों की अपनी सुरक्षा रहेगी, राह चलते लोगों के लिए भी उनकी पहल मददगार साबित होगी।

अक्षयवट समेत 16 प्रमुख स्थलों पर लगेंगे बैगेज स्कैनर

प्रयागराज। कुम्भ में सुरक्षा और जांच उपकरण भी अत्याधुनिक होंगे। मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा का जाल बिछाया जा रहा है। अक्षयवट व बड़े हनुमान मंदिर समेत प्रमुख शिविरों में प्रवेश से पहले सामानों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कोई भी संदिग्ध वस्तु लेकर प्रमुख स्थलों में नहीं जा सकेगा। अक्षयवट समेत 16 प्रमुख शिविरों के बाहर बैगेज स्कैनर लगेंगे। इसकी खरीदारी भी कर ली गई है। कुम्भ में सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख प्रवेशद्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाने की योजना थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी समीक्षा की तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर इसमें बदलाव किया गया। इस बीच अक्षयवट के खोले जाने के बाद एक बार फिर सैन्य अधिकारियों व सुरक्षा एजेसियों की बैठक हुई। इसके बाद बैगेज स्कैनर लगाने की योजना में बदलाव किया गया। अब प्रमुख प्रवेशद्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाने की जगह प्रमुख मंदिरों व शिविरों के बाहर लगाया जाना है। एयरपोर्ट की तरह की इन प्रमुख स्थलों पर सामानों की चेकिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सुरक्षा कारणों से प्रमुख जगहों पर बैगेज स्कैनर लगाया जाना है। हाईकोर्ट शिविर और मुख्यमंत्री के शिविर से पहले दो-दो स्कैनर लगने हैं। इसी तरह अक्षयवट, बड़े हनुमान मंदिर, वैदिक संस्कृति ग्राम और टेंट सिटी में दो-दो स्कैनर लगेंगे।

एक्वा लाइन मेट्रो का अधिकतम किराया होगा 50 रुपये, सुरक्षा में भी होगा बड़ा बदलाव

ग्रेटर नोएडा एजेंसी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) की शुक्रवार को हुई 18वीं बोर्ड बैठक में नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो के किराये के प्रस्ताव को हरी झंडी प्रदान कर दी गई।
एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक आलोक टंडन ने बताया कि न्यूनतम किराया 10 रुपये तथा अधिकतम किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है।

उन्होंने बताया कि एक्वा लाइन मेट्रो रेल को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा गया है। जैसे ही शासन से इसके उद्घाटन की तिथि तय हो जाएगी इसकी शुरुआत कर दी जाएगी।

स्मार्ट कार्ड से मिलेगी 5 फीसदी छूट

बोर्ड द्वारा मंजूर किराया सूची में दो स्टेशन के लिए 15 रुपये, 3-6 स्टेशन के बीच 20 रुपये, 7-9 स्टेशनों तक 30 रुपये, 10-16 स्टेशनों के लिए 40 रुपये तथा 17 एवं उससे अधिक स्टेशनों के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये किराया निर्धारित किया गया। वहीं स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए न्यूनतम किराया नौ रुपये तथा अधिकतम 45 रुपये तय किया गया है। यानी स्मार्ट कार्ड धारकों को अन्य लोगों के मुकाबले 5 फीसदी की किराये में छूट मिलेगी।

पीएसी संभालेगी सुरक्षा की कमान

उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में मेट्रो कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई निर्णय लिए गए।

मेट्रो की सुरक्षा के लिए उ.प्र. पीएसी की 49वीं वाहिनी को तैनात किया जाएगा।

इसके अलावा कुछ निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए जाएंगे जिनका प्रशिक्षण सीआईएसएफ द्वारा कराया जा रहा है। सुरक्षा बलों का वेतन राज्य सरकार वहन करेगी।

सुरक्षाबलों के लिए 800 भवन खरीदे जाएंगे

प्रबंध निदेशक ने बताया कि मेट्रो सुरक्षाबलों की आवासीय व्यवस्था के लिए नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 800 भवन मुहैया कराए जाएंगे। यह आवास एनएमआरसी को खरीदने पड़ेंगे।

एनएमआरसी की बोर्ड बैठक में नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-5 यानी 14.95 किलोमीटर के मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव को शासन को भेजने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वर्ष 2017-18 की बैलेंस शीट एवं वार्षिक लेखा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

एक्वा लाइन मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से मॉल में भी कर सकेंगे शॉपिंग

बोर्ड बैठक में केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा ओएसडी मुकुंद कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव झंजा त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण, शहरी विकास मंत्रालय के अनुसचिव दीनदयाल, रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक शैलेश जैन, यूपी पीएसी की कमांडेंट कल्पना सक्सेना, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ए.के. श्रीवास्तव, एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक पी.डी. उपाध्याय तथा कंपनी सचिव निशा बधावन आदि मौजूद थीं।

संपादकीय

नीति आयोग ने अपने रणनीतिक दस्तावेज में 2022-23 तक हर साल आठ प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आयोग चाहता है कि अर्थव्यवस्था को चार लाख करोड़ डॉलर का बनाया जाए और केंद्र सरकार आठ प्रतिशत की जगह सीधे नौ प्रतिशत के विकास दर को पाने के लिए कोशिश करे। निश्चित रूप से यह रणनीतिक दस्तावेज सरकार के एजेंडे को पूरा करने में मददगार होगा।

सही रास्ते पर है नीति आयोग

नीति आयोग ने अपने रणनीतिक दस्तावेज में 2022-23 तक हर साल आठ प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आयोग चाहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चार लाख करोड़ डॉलर का बनाया जाए और सरकार आठ प्रतिशत की जगह सीधे नौ प्रतिशत के विकास दर को पाने के लिए कोशिश करे। जाहिर है, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार को शिद्दत से कोशिश करनी होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने मौजूदा कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो लक्ष्य से कुछ कम है। हालांकि, वित्त वर्ष 2015-16 में आठ प्रतिशत की वृद्धि दर को हासिल किया जा चुका है। लिहाजा, विगत चार सालों में किए गए आर्थिक सुधारों को देखते हुए नीति आयोग के अनुमानों को अतिरंजना से परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। रणनीतिक दस्तावेज को पेश करने से पहले नीति आयोग ने 2107-18 से 2019-20 के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना जारी किया था, लेकिन इनसे सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को नहीं हासिल किया जा सकता था। इसलिए, अब पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग ने न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए रणनीतिक दस्तावेज पेश किया है।

नीति आयोग के रणनीतिक दस्तावेज के अनुसार निवेश को जीडीपी के मौजूदा 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022-23 तक 36 प्रतिशत किया जाएगा। इस महती कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार बुनियादी क्षेत्रों में निवेश करेगी। इस वृद्धि दर के लक्ष्य को पाने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को मौजूदा 478 अरब डॉलर से बढ़ाकर 800 अरब डॉलर करने का लक्ष्य भी मोदी सरकार ने रखा है। कृषि की अड़चनों को दूर करने, किसानों को कृषक उद्यमी बनाने, श्रम कानूनों को संहिता का रूप देने तथा उद्यमियों के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग एवं सहायता मुहैया कराने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिए जाने का प्रस्ताव है। रणनीतिक दस्तावेज में वित्त वर्ष 2022-23 तक मुद्रास्फीति को दो से छह प्रतिशत के दायरे में रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुद्रास्फीति कम रहने पर देश में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जा सकेगा और आम आदमी भी महंगाई डायन के चंगुल से आजाद रह सकता है। इसी क्रम में माल ढुलाई बढ़ाने एवं रेल विकास प्राधिकरण को स्थापित करने का प्रस्ताव भी दस्तावेज में किया गया है।

रणनीतिक दस्तावेज में कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज माफी या आय के प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार का मकसद कृषि ऋण को माफ करने के बजाय उनकी समस्याओं को दूर करना है। अस्तु, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2015-16 से 2022-23 के दौरान कृषि क्षेत्र में 10.4 प्रतिशत के विकास दर को हासिल करने की सरकार हर संभव प्रयास करेगी। दस्तावेज में एपीएमसी कानूनों में संशोधन करने की बात कही गई है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। सरकार चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह न्यूनतम आरिक्षत मूल्य की अवधारणा देश में लाई जाए। इससे किसानों को उनकी उपज की वास्तविक कीमत मिल सकेगी। रणनीतिक दस्तावेज में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव लाकर उसे मौसम आधारित बीमा योजना में तब्दील करने की बात कही गई है। इससे फसल बर्बाद होने पर किसानों को वाजिब मुआवजा मिल सकेगा। विभिन्न मंडियों में नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था करने की भी सरकार कोशिश करेगी, ताकि किसानों का बिचौलिया शोषण नहीं कर सके।

सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने का प्रयास सरकार करेगी। रणनीतिक दस्तावेज में एक लाख 50 हजार स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर के साथ आयुष्मान भारत कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कराने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्रों में सस्ते आवास के लिए आने वाले वर्षों में सरकार सब्सिडी के माध्यम से आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने की कोशिश करेगी। सरकार चाहती है कि रणनीतिक दस्तावेज के बाद दृष्टि पत्र जारी किया जाए। इसमें अगले 15 सालों के लिए भारत की विकास की गति का खाका खींचा गया है। रणनीतिक दस्तावेज में कहा गया है कि वैश्विक व्यवहार के मुताबिक किसी कामगार की सेवा समाप्त होने पर उसे मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार को न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी तरह के रोजगारों को शामिल करना चाहिए। कामगारों को चेक या फिर आधार के माध्यम से वेतन का भुगतान करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। दस्तावेज में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुनी कर 2022-23 तक दो लाख किलोमीटर तक बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक औसतन सालाना आठ प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को देश में समावेशी विकास करने की दिशा आगे बढ़ना होगा। निवेश को 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत करने के लिए सरकार को नीतिगत माहौल बनाना होगा साथ ही साथ कारोबारी एवं सरकार दोनों को मामले में सकारात्मक तरीके से काम करना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मानते हैं कि ठोस आर्थिक एवं सामाजिक नीति बनाकर गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनके अनुसार ठोस नीति अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती है। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने पर स्वतः गरीबी दूर हो जाएगी। जेटली ने कहा कि हमने जो तरीका अख्तियार किया है, उसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। वित्त मंत्री के अनुसार रणनीतिक दस्तावेज का लक्ष्य जीडीपी की वृद्धि दर को आठ प्रतिशत करना है। साथ ही, इसका लक्ष्य देश को 2030 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है, ताकि सरकार के सुधार के सभी उपायों को पूरा किया जा सके और लक्ष्य पूरा हो सके।

नीति आयोग के अनुसार देश में डिजिटलीकरण को मूर्त देने के लिए ब्राडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल पहुंच तथा साक्षरता की समस्याओं से पार पाने एवं साइबर सुरक्षा मसौदे को और मजबूत करने की जरूरत है। दस्तावेज में 2022-23 तक डिजिटल क्षेत्र में असमानता दूर करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा की अहमियत को रेखांकित किया गया है। रणनीतिक दस्तावेज में सड़क क्षेत्र के लिए सार्वजनिक वाहनों के बेड़े का विस्तार, राजमार्ग नेटवर्क एवं सड़क क्षमता को बढ़ाने और बेहतर अनुपालन के लिए नियामकीय मसौदे में सुधार आदि सुझाव दिए गए हैं। बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए स्मार्ट ग्रिड को बढ़ावा देने, बिजली की नीलामी, बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सब्सिडी का भुगतान करने तथा बिजली आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत मीटर लगाने के सुझाव दिए गए हैं। साफ है, बिना सपना देखे देश में बदलाव नहीं आ सकता है। मामले में रणनीतिक दस्तावेज को आम आदमी के सपने की संज्ञा दी जा सकती है।

मोदी सरकार देश में खुशहाली लाने का सपना देख रही है। अगर सरकार योजनाबद्ध तरीके से रणनीतिक दस्तावेज में सुझाए गए उपायों को अमल में लाती है तो निश्चित रूप से देश में जल्द ही खुशहाली आ सकेगी। निश्चित रूप से नीति आयोग ने जो रणनीतिक दस्तावेज तैयार किया है, उस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि सरकार के एजेंडे को शत-प्रतिशत पूरा करने में कोई कसर बाकी न रहे।

सतीश सिंह
(आर्थिक मामलों के जानकार)

विचार

खुदरा व्यवसाय को मिलेगी गति

ऑनलाइन कंपनियों जैसे अमेजन व फ्लिपकार्ट आदि पर अब किसी भी उत्पाद की एक्सक्लूसिव बिक्री नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए इस तरह की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे खुदरा व्यापारियों को समान प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। दरअसल, कंपनियां बाजार में अच्छी कंपनियों के आने वाले प्रमुख उत्पाद की एक्सक्लूसिव सेल लगाती थीं। इससे एक तरफ उत्पाद निर्माता कंपनी का मुफ्त में प्रचार हो जाता था, तो वहीं ट्रांसपोर्टेशन और अन्य कीमत न होने से ऑन-लाइन कंपनी को उत्पाद का मूल्य कम पड़ता था। इससे वे बहुत कम मार्जिन पर सामानों की बिक्री करती थीं। इससे उत्पाद निर्माता कंपनी और ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनी दोनों को अच्छा लाभ हो रहा था। इस वर्ग में खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे जा रहे थे। इससे इन नए उत्पादों को बाद में खुदरा बाजार में आने पर भी बहुत कम ग्राहक उसके पास जा रहे थे। खुदरा व्यापारियों का बिजनेस ठप होने की स्थिति आ गई थी। व्यापारियों ने सरकार से गुहार लगाई थी।

देश में खुदरा बाजार बहुत बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग चार करोड़ खुदरा की दुकानें हैं। इनके माध्यम से लगभग चौदह करोड़ लोगों का रोजी-रोटी जुड़ी है। जीएसटी के कारण पहले ही सरकार से नाराज चल रहे व्यापारी ऑनलाइन कंपनियों पर कोई लगाम न लगाए जाने से भी नाराज चल रहे थे। सरकार ने जीएसटी की दर घटाकर व्यापारियों को मनाने का काम किया था। इस नए कानून के द्वारा भी उसने इसी वर्ग को रिझाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आरएसएस और स्वदेशी जागरण मंच भी सरकार पर देशी कंपनियों, खुदरा व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही थी। इससे भी सरकार पर दबाव काम आया और इसका अंत इस कानून के साथ हुआ। देश में इंटरनेट सेवा का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण देश में चौथी श्रेणी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ ऑनलाइन बाजार प्रति वर्ष आठ से दस फीसदी की दर से आगे बढ़ रहा है।

2013 में भारत में 2.3 बिलियन डालर का ऑनलाइन बिजनेस हुआ था। आने वाले समय में चीजों की बिक्री ऑन लाइन बढ़ने और खुदरा बाजार का नुकसान होने की संभावना लगातार बढ़ रही थी। इसलिए भी सही समय पर ऑनलाइन बाजार से जुड़े नियम कायदे सबके हित में बनाने की मांग उठ रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग और जीएसटी के बाद खुदरा व्यापारियों की कमर टूट गई थी। छोटे दुकानदारों की नाराजगी का अंदाजा सरकार को भी था। इस दिशा में काम काफी दिनों से चल रहा था। अब उस पर मुहर लग गई है। खुदरा दुकानों को इस फैसले से राहत मिलेगी और व्यापारियों का गल्ला भी भारी होगा। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ठगी के शिकार हो रहे लोगों को भी छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय में एकरूपता के लिए अब भी काफी कुछ किया जाना शेष है।

उद्देश्यों से भटक रहा आईपीएल

अगले साल होने वाले आईपीएल के 12वें सत्र के लिए टीमों ने बोली लगाकर खिलाड़ियों को खरीद लिया है। अगले साल यह लीग उस समय होगी जब क्रिकेट विश्व कप और लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे, ऐसे में दर्शकों का मोहभंग होना स्वाभाविक है। हालांकि, इस लीग के प्रति दर्शकों के मोहभंग का कारण एक नहीं कई हैं। खेल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा और सट्टेबाजी ने क्रिकेट के नए संस्करण को बदतर बना दिया है।

क्रिकेट विधा का सबसे विवादित संस्करण इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के अलावा आईपीएल के दामन में कई दाग लगे हैं। इसे खत्म करने की भी मांग बीच में उठती रही है लेकिन आईपीएल कमाई का ऐसा जरिया बन चुका है जिससे किसी का मोह ही नहीं छूट रहा। सीजन पांच से लेकर पिछले साल के आंकड़ों पर गौर करें तो दर्शक इस खेल से लगातार दूरी बनाते जा रहे हैं, पर बावजूद इसके आयोजक आईपीएल को खींचे जा रहे हैं। पिछले दो संस्करणों से खेल के प्रति नीरसता ज्यादा बढ़ी है। आईपीएल-12 का आयोजन इस बार आम चुनाव और क्रिकेट विश्व कप के वक्त किया जा रहा है इसलिए यह निश्चित है कि दर्शक इस बार ज्यादा रुचि नहीं लेंगे।

खैर, पूर्व के विवादों पर ध्यान न देते हुए टीम मालिकों ने क्रिकेट की मंडी में एक बार फिर देशी-विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी मेले में अपने खिलाड़ियों की बोलियां लगा दीं। सभी टीम प्रबंधकों ने अपने-अपने पंसद के कई खिलाड़ियों पर बोली लगाकर आईपीएल के 12वें संस्करण के लिए खरीदारी कर टीमों का चुनाव किया है। अगले साल आयोजित होने वाले आईपीएल के नए एडीशन के लिए जयपुर में सैकड़ों क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी हुई। पिछले साल की तरह आईपीएल-12 के सीजन में भी आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें करीब 350 खिलाड़ी अपना कौशल प्रदर्शित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। क्रिकेट पंडितों की मानें तो आगामी आईपीएल आयोजन का रंग कुछ फीका रहने की उम्मीद है क्योंकि कई वरिष्ठ खिलाड़ी इस सीजन से दूरी बनाए हुए हैं। वह इसलिए मई माह से ही आईसीसी विश्वकप का महाकुंभ शुरू होगा। सीनियर खिलाड़ियों ने विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर ऐसा फैसला लिया है, तो कुछ खिलाड़ी फिटनेस के चलते भाग नहीं ले रहे और कुछ की बोली नहीं लग सकी है। इसलिए आयोजकों की बड़ी परीक्षा दर्शकों को एकत्र करने की होगी।

हर सत्र में आईपीएल को खेल से नहीं बल्कि सीधे व्यापार से जोड़कर देखा जाता है। चारों ओर धन की वर्षा होती है। खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट बोर्ड, प्रबंधक, सट्टेबाज व जुआरी आदि विभिन्न तरीकों से लोग इस खेल के जरिए पैसा कमाते हैं। आईपीएल के खेल की एक-एक गेंद पर लोग पैसों की बोली लगाते हैं। यही वजह है इस खेल का क्रेज अब दिनों-दिन खत्म होता जा रहा है। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ आईपीएल के शुरू होने का इंजतार करते हैं क्योंकि उनको नेशनल टीम में खेलने का तो मौका नहीं मिलता लेकिन एक-डेढ़ माह के आईपीएल में खेलकर अच्छा कमा लेते हैं। हालांकि, एक बात यह भी सच है इस खेल के जरिए कई खिलाड़ियों ने नेशनल टीम में भी जगह बनाई है। आईपीएल के शुरुआती एक-दो संस्करण का क्रेज देशवासियों में सिर चढ़कर बोला लेकिन जैसे ही इस खेल की असल सच्चाई सामने आई तो लोगों का मोह खत्म होता है। देखा जाए तो, आईपीएल की चमक फीकी होने का एक कारण यह भी रहा कि आईपीएल अपने शुरुआत से लेकर अब तक भयंकर विवादों में घिरा रहा।

इस बार कुछ बड़े खिलाड़ियों ने खुद रिटेन होने की अर्जी दी। उनमें महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, मुरली विजय, रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, अंबाती रायुडू, हरभजन सिंह और दीपक चाहर शामिल हैं। इनके अलावा केएम आसिफ, कर्ण शर्मा, ध्रुव शौरी, मोनू कुमार, चैतन्य विश्नोई, एन जगदीशन, शार्दुल ठाकुर, मोहित शर्मा व ऋतुराज गायकवाड़ ने भी खुद की बोली लगाने के लिए आयोजकों से संपर्क किया। विदेशी खिलाड़ियों में सैम बिलिंग्स, इमरान ताहिर, फॉफडुप्लेसी, मिचेल सेंटनर, डेविड विली, ड्वेन ब्रावो, शेन वॉटसन, लुंगी नगिडी आदि को रिटेन किया गया है। प्रबंधकों ने इस बार युवा और नए खिलाड़ियों पर ज्यादा विश्वास जताया है। बड़े खिलाड़ियों को ज्यादा भाव नहीं दिया। जो कभी सबसे महंगे बिकते थे उनकी बोली सबसे कम लगाई गई है, उनमें युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। युवराज कभी 16 करोड़ रुपए में बिके थे लेकिन इस बार महज एक करोड़ में ही बिके।

आयोजकों के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती दर्शकों को जोड़ने की होगी क्योंकि जिस वक्त आईपीएल शुरू होगा उसी वक्त देश में लोकसभा चुनाव और वर्ल्ड कप की गहमागहमी होगी। आईपीएल-2019 की नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और जयदेव उनादकट सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। वरुण चक्रवर्ती को 8.4 करोड़ रुपए में पंजाब ने और जयदेव उनादकट को भी 8.4 करोड़ रुपए में ही राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। टीम प्रबंधक इस बार कुछ प्रयोग करना चाहते हैं इसलिए नीलामी में युवा खिलाड़ियों पर जोर दिखाया। नए खिलाड़ी शिवम दुबे को आरसीबी ने पांच करोड़ रुपए में खरीदा है तो वहीं 17 साल के प्रभसिमरन और 4.80 और 15 साल के प्रयास को 1.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया।

जयपुर में क्रिकेट खिलाड़ियों के बिकने के लिए लगाया नीलामी मेला खत्म तो हो गया है, लेकिन खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं एक सामान्य स्तर की नीलामी और होगी। दरअसल कुछ खिलाड़ी बिकने को रह गए हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको खरीदारों ने नकारा है। इस बार वह क्रिकेटर बेभाव बिके हैं जिन्हें पिछले संस्करणों में कोई पूछता तक नहीं था। धुरंधरों की कीमत न लगने को आईपीएल इतिहास में बड़ा बदलाव कहा जा रहा है। इस बार अनकैप्ड प्लेयर्स दिग्गजों पर भारी पड़े। कह सकते हैं कि टीम मालिकों ने आईपीएल के इस 12वें सीजन में खिलाड़ियों के खरीदने का पैमाना पूरी तरह से बदल दिया। देखा जाए तो दर्शक भी अब आईपीएल में नए चेहरों को देखना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि दशकों की चाहत को पूरा करने के लिए ही टीम मालिकों ने इस बार यह बदलाव किया है।

गौरतलब है कि क्रिकेटप्रेमियों के अलावा बीसीसीआई और देश-दुनिया के ढेरों क्रिकेट खिलाड़ियों को आईपीएल का इंतजार बेसब्री से रहता है। इंतजार हो भी क्यों न, लीग कमाई और शोहरत का जरिया जो बन गई है। इस खेल में खिलाड़ियों के लिए बेशुमार पैसा है। यही वजह है कि आईपीएल ने कई बड़े और छोटे अनजान चेहरों को नई पहचान दी है। लीग में चारों ओर पैसा बरसता है इसलिए हर कोई इस चमत्कारी आयोजन से जुड़कर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। पूर्व में इस लीग के 11 सेशन संपन्न हो चुके हैं। अब 12वें सत्र की बारी है। टीम प्रबंधकों ने आईपीएल-12 के लिए आयोजन में कुछ बदलाव किया है। टीम मालिकों ने ऐसे चेहरों को शामिल किया है जिनकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। अब देखना है कि वे खेल के दौरान अपने मालिकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं। जो भी हो आईपीएल की चमक-दमक में कई खिलाड़ी छाप जरूर छोड़ जाते हैं।

आईपीएल के पहले दो संस्करणों में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। उसके बाद खेल में भ्रष्टाचार शामिल हुआ, तो दर्शकों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। अब यह खेल हर साल औपचारिकता निभाने भर का रह गया है। खेल के प्रति लोकप्रियता गायब है। क्रिकेट के दूसरे मैचों में आज भी रोमांच दिख जाता है, मगर आईपीएल में नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि जिस भावना को लेकर इस लीग की शुरुआत की गई थी, उसे बरकरार रखा जाए। नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए आईपीएल का जन्म हुआ था, मगर अब यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनकर रह गया है। इससे उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

रमेश ठाकुर
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

खुदरा व्यापारियों का यह सोचना गलत है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही। देश में सभी को अपना कारोबार करने का मौका दिया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा।

रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री

ऑनलाइन कारोबार को बढ़ावा देने के एवज में छोटे दुकानदारों का हक जिस तरह से मारा जा रहा था, वह गलत था। अब यह उम्मीद है कि वे राहत में रहेंगे।

श्वेता, वरिष्ठ पत्रकार

सत्यार्थ

शत्रु को मित्र बनाने का तरीका

अमेरिका के महान सेनापति थे, जनरल रॉबर्ट एडवर्ड ली। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन ने उनसे उनके एक अधीनस्थ अधिकारी के बारे में राय मांगी। जनरल ली बोले-सर, निःसंदेह वह अधिकारी बेहद कुशल एवं जिम्मेदार व्यक्ति है और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण व निष्ठा के साथ करता है। उसको जो भी कार्य दिया जाए, वह उसे समय से पहले ही पूरा कर लेता है। यह सुनकर जेफरसन बेहद खुश हुए। उन्होंने उस अधिकारी को किसी योग्य पद के लिए चुनने का मन बन लिया। राष्ट्रपति के जाने के फौरन बाद वहीं खड़े एक अधिकारी ली के पास आकर बोले- सर, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आपने उस अधिकारी की बहुत तारीफ क्यों की? ली बोले-मैंने सही तो कहा है। वह सचमुच निष्ठावान व योग्य है। जो जैसा है, उसके बारे में वैसा ही तो कहा जाएगा। यह सुन कर अधिकारी और अधिक हैरान हो गया और बोला-सर, आप भलीभांति जानते हैं कि वह अधिकारी तो आपके प्रति शत्रुता का भाव एवं नकारात्मक विचार रखता है। इस पर ली बोले-तो क्या हुआ? राष्ट्रपति ने उस अधिकारी के बारे में मेरे विचार पूछे थे, मेरे बारे में उसके विचार नहीं पूछे थे। शत्रु अधिकारी को जब यह पता चला कि राष्ट्रपति के सामने उसके कार्य की बेहद प्रशंसा की गई है और यह प्रशंसा रॉबर्ट ली ने की है, तो वह बेहद लज्जित हुआ। इसके बाद तो उस अधिकारी ने ली के प्रति शत्रुता का भाव निकाल दिया व मन से भी अच्छा बन गया। इस प्रकार जनरल ली के विचारों ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के मन से नकारात्मक विचारों और शत्रुता के भावों को हमेशा के लिए निकाल दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि शत्रु को बल से नहीं, बल्कि विचारों से जल्दी हराया जा सकता है।

रेनू सैनी

सार समाचार

अमेरिका: कोहेन ने प्राग में रूसी अधिकारियों से मुलाकात की बात को नकारा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व अटॉर्नी माइकल कोहेन ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान प्राग में रूसी अधिकारियों के साथ मुलाकात से इनकार किया है। कोहेन ने गुरुवार को अपने ट्वीट में कहा, 'मैं कभी प्राग नहीं गया। मुलर सब जानते हैं।'

रॉबर्ट मुलर अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के पूर्व निदेशक हैं जो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रंप को चुनाव जिताने के लिये उनके प्रचार में रूस का हाथ था। कोहेन ने यह ट्वीट मैकक्लाची न्यूज सर्विस की उस खबर के बाद किया जिसमें कहा गया था कि कोहेन के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह 2016 की गर्मियों में प्राग के पास थे। इससे इन दावों को बल मिलता है कि उन्होंने वहां रूसी अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसी महीने कर चोरी और दूसरे अपराधों में तीन साल जेल की सजा पाने वाले कोहेन ने कहा कि वह कभी भी प्राग नहीं गए।

बुर्किना फासो में घात लगाकर किए गए हमले में 10 पुलिस अधिकारियों की मौत

वागाडुगू। बुर्किना फासो के उत्तरपश्चिम क्षेत्र में घात लगाकर किए गए हमले में दस पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पश्चिम अफ्रीकी देश के सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''दस अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी और तीन घायल हो गए।'' बयान में कहा गया है कि तोएनी क्षेत्र के पुलिस के एक काफिले और वागाडुगू इलाके के अतिरिक्त बलों पर घात लगाकर हमला किया गया। एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि अधिकारियों पर तब हमला किया गया जब वे माली के साथ लगती सीमा के समीप लोरोनी गांव जा रहे थे। गांव में सशस्त्र हमलावरों ने एक स्कूल पर हमला कर दिया था और उनकी पाठ्य पुस्तकों को जला दिया था। सूत्र ने बताया कि घायलों में दो की हालत गंभीर है और उन्हें देडुगू के एक अस्पताल ले जाया गया। बुर्किना फासो में पिछले तीन वर्षों से घातक हमले तेजी से बढ़ रहे हैं।

अमेरिका में तूफान से सैकड़ों उड़ानें रद्द, छुट्टियां मना रहे लोग परेशान

शिकागो। अमेरिका के मध्य भाग से सर्दियों में आने वाले एक शक्तिशाली तूफान के गुजरने से बृहस्पतिवार को देशभर में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं और हजारों उड़ानों में देरी हुई जिससे क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे यात्री परेशान हुए। उड़ानों की निगरानी रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, 6,500 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और करीब 800 उड़ानें रद्द कर दी गईं। देश के उत्तरी और मध्य मैदानी भागों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण भी सड़क मार्ग से यात्रा करना खतरनाक हो गया। कुछ इलाकों में शुक्रवार को तूफान के कमजोर पड़ने से पहले एक फुट से अधिक की बर्फ देखी गई। अधिकारियों ने नेब्रास्का के कुछ हिस्सों में दृश्यता बेहद कम होने की जानकारी दी है और एक अंतरराज्यीय सड़क को बंद कर दिया है। नॉर्थ डकोटा ने राज्य के पूर्वी हिस्से की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है।

भूटान का 'नैरोइंग द गैप' और भारत का 'सबका साथ, सबका विकास' का विजन एक जैसा: पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा. यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटान के समकक्ष लोटे शेरिंग के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद की गई, जिसमें हिमालयी राजशाही में विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई. मोदी ने बैठक के बाद शेरिंग के साथ मीडिया को संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी करने हुए कहा, ÷मैंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि भारत, भूटान के विकास में एक विश्वस्त सहयोगी और भागीदार की भूमिका निभाता रहेगा.'

उन्होंने कहा, 'भारत, भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा. यह योगदान भूटान की जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से किया जाएगा.' भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना साल 2018 से 2023 तक चलेगी. मोदी ने कहा कि शेरिंग ने जिस 'नैरोइंग द गैप' विजन का उल्लेख किया है, वह उनके 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन से मेल खाता है. उन्होंने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं का विकास भारत द्वारा की जा रही लंबे समय से भूटान की मदद का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

मोदी ने कहा, 'आज हमने हमारी मदद द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा की.' उन्होंने कहा कि भूटान में 720 मेगावॉट की मंगडेछु जलविद्युत परियोजना जल्द ही पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पैदा होनेवाली बिजली के टैरिफ को लेकर दोनों देशों में सहमति है. उन्होंने भूटान द्वारा भारत के रुपे कार्ड को जल्द ही अपने यहां लांच करने के फैसले का स्वागत किया तथा कहा कि इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा.

वहीं, शेरिंग ने कहा कि भारत-भूटान राजनयिक संबंधों के स्वर्ण-जयंती वर्ष पर होने वाली उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है. उन्होंने पंचवर्षीय योजना के लिए भारत द्वारा दी जाने वाली मदद की सराहना की और कहा कि इससे भारत द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण प्रभावित हुए व्यापारियों को मदद मिलेगी. उन्होंने मोदी को कुछ ही महीनों में पूरा होने वाले मंगडेछु परियोजना के उद्घाटन के लिए भूटान आने का आमंत्रण दिया. शेरिंग शुक्रवार को भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए हैं, जो कि अक्टूबर में पद संभालने के बाद उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है.

अमेरिकी सरकार का कामकाज अगले सप्ताह भी रहेगा ठप

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी सरकार का कामकाज अगले सप्ताह भी ठप रहेगा। सांसद अमेरिका-मेक्सिको सीमा दीवार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को लेकर पैदा हुए गतिरोध को बृहस्पतिवार को भी हल करने में विफल रहे जिसके बाद यह संकट और गहरा गया है। क्रिसमस की आधिकारिक छुट्टी के बाद कुछ मिनट के लिए बुलाई गई सीनेट की बैठक में अगले बुधवार को बजट पर चर्चा करने का फैसला किया गया। यह रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली कांग्रेस का आखिरी दिन होगा। इसके साथ ही सरकार का कामकाज 12 दिन तक ठप रहना तय लग रहा है।

डेमोक्रैट्स ने ट्रंप की सीमा पर दीवार बनाने की परियोजना के लिए पांच अरब डॉलर देने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति इस बात जोर दे रहे हैं कि जब तक उन्हें धन नहीं मिलेगा तब तक वह सरकार को बजट नहीं देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने डेमोक्रैट्स पर अमेरिकी नागरिकों के बजाय अवैध शरणार्थियों की रक्षा करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि ट्रंप उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जिसमें हमारी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस संकट के चलते करीब 800,000 संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर एक बार फिर डेमोक्रैट्स पर आरोप लगाया कि वे अवैध शरणार्थियों, खुली दक्षिणी सीमा और वहां से होने वाले अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''मादक पदार्थ, मानव तस्करी, हमारे देश में आ रहे गिरोह के सदस्यों और आपराधियों को रोकने की जरुरत है।'' वह दीवार बनाने में डेमोक्रैट सांसदों द्वारा बाधा डालने पर भी उन पर जमकर बरसे।

उनकी रिपब्लिकन पार्टी समेत विरोधियों ने राष्ट्रपति पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अवैध शरणार्थियों से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। एक वरिष्ठ डेमोक्रैट सीनेटर ने ट्वीट कर कहा, ''उन्होंने दीवार बनाने के लिए पांच अरब डॉलर की बेहूदी मांग को लेकर हमारी सरकार को बंधक बना लिया है। यह दीवार बेकार और अप्रभावी साबित होगी।'' गौरतलब है कि अमेरिका में बजट को लेकर मोलभाव में सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप करना कोई असामान्य हथियार नहीं है।

अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों ने अली रजा आबिदी के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की

वाशिंगटन (एजेंसी)।

संसद के पूर्व सदस्य अली रजा आबिदी की हत्या से चिंतित आत्म निर्वासन में अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी असंतुष्टों के एक समूह ने उनके हत्यारों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की है। साउथ एशियन्स अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएटीएच) की संचालन समिति के सदस्यों ने गुरुवार को आबिदी की हत्या पर एक बयान में कहा, ''हम पूर्व सांसद और एमक्यूएम के वरिष्ठ नेता सैयद अली रजा आबिदी की जघन्य हत्या से सकते में हैं और आतंकित हैं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।'' आबिदी की कराची में उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो बंदूकधारियों ने रविवार को हत्या कर दी थी। यह घटना उस वक्त हुई थी जब वह अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे।

एसएएटीएच ने कहा, ''यह हत्या पाकिस्तानी प्रतिष्ठान और कृत्रित रूप से चुनी गई इसकी असैन्य सरकार की ओर से कराची में शांति और सुरक्षा बहाल करने के झूठे दावों के बीच हुई है।'' संगठन ने कहा, ''हम हत्यारों को न्याय के दायरे में लाने की मांग करते हैं। सिर्फ इस खेल के प्यादों को ही नहीं बल्कि सरगनाओं को भी न्याय के दायरे में लाया जाए।''

संगठन ने पाकिस्तान के भीतर नागरिक अधिकारों और असहमति की घटती गुंजाइश पर वाशिंगटन डीसी में हाल में एक सम्मेलन का भी आयोजन किया था। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में स्तंभकार गुल बुखारी और डॉ. मोहम्मद ताकी, निर्वासित पत्रकार तहा सिद्दीकी और अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी समेत संगठन की 28 सदस्यीय संचालन समिति के अन्य सदस्य शामिल हैं।

एक अलग बयान में वॉइस ऑफ कराची के अध्यक्ष नदीम नुसरत ने आबिदी की हत्या के लिये साफ तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य थॉमस गैरेट ने भी एक ट्वीट करके आबिदी की हत्या की निंदा की।

चीन में मानवाधिकार कार्यकर्ता की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन में मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं वकील वांग कुआनझांग की पत्नी ली वेंजू को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने से पुलिस ने शुक्रवार को रोक दिया। वह वांग के खिलाफ चल रहे केस में तिआनजिन कोर्ट द्वारा न्यायिक नियमों के उल्लंघन को लेकर शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रही थीं।

देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में वांग को वर्ष 2015 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पिछले तीन वर्षों से उन्हें परिवार और वकील से मिलने नहीं दिया गया। ली ने कहा, 'यह हास्यास्पद है कि शीर्ष न्यायालय के परिसर में करीब 30 पुलिसकर्मियों ने मुझे और मेरे साथ आए दर्जन भर लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने से रोक दिया।

आप यह सब देख सकते हैं कि किस प्रकार कानून के शासन के नाम पर यह कार्रवाई की जा रही है। यह कितना दूर्भाग्यपूर्ण है।' बीते गुरुवार को वांग के खिलाफ उत्तरी चीन स्थित तिआनजिन जिला कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई की थी। सुनवाई में शामिल होने से रोकने के लिए ली को बीजिंग स्थित उनके फ्लैट में नजरबंद कर दिया गया था।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर पाक की सफाई, कहा- इसका कोई सैन्य पहलू नहीं

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) एक द्विपक्षीय आर्थिक परियोजना है और इसे सैन्य नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने यह बात गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका की उस रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल के जवाब में कही जिसमें आरोप लगाया गया है कि चीन 60 अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना के तहत पाकिस्तान में लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य हथियार बनाने की गुप्त योजना पर काम कर रहा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना और चीन के अधिकारी इस गुप्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिये तैयार हैं. हालांकि चीन ने पिछले सप्ताह इस रिपोर्ट को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया था.

पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन ने फैसल के हवाले से कहा, 'सीपीईसी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खासतौर पर इसके तहत आने वाले ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में सुधार किया है. सीपीईसी द्विपक्षीय आर्थिक परियोजना है, जो किसी देश के खिलाफ नहीं है.' पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह और चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाला सीपीईसी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना है.

सुषमा की पाकिस्तान को दो टूक, 'बातचीत का माहौल आतंक और दुश्मनी से मुक्त हो'

नई दिल्ली (एजेंसी)।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सार्थक द्विपक्षीय बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है. उन्होंने कहा कि बातचीत का माहौल आतंक, दुश्मनी तथा हिंसा से मुक्त होना चाहिए. राज्यसभा में शिवसेना के सांसद अनिल देसाई के एक सवाल के लिखित जवाब में स्वराज ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से स्पष्ट कर दिया है कि एक सार्थक बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और यह माहौल आतंक, दुश्मनी तथा हिंसा से मुक्त होना चाहिए.

देसाई ने सवाल किया था कि पाकिस्तान की निरंतर आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए पिछले तीन साल में भारत ने उसके खिलाफ क्या-क्या दंडात्मक आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगाए हैं.

स्वराज ने कहा, ''पाकिस्तान की ओर से सीमा पर निरंतर हो रही आतंकवादी घटनाएं भारत के लिए गहरी चिंता का विषय बनी हुई है. पाकिस्तान सरकार से लगातार आग्रह किया गया है कि वह अपने नियंत्रण में आने वाले किसी भी भूक्षेत्र का किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दे.''

विदेश मंत्री ने कहा, ''भारत सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ और पाकिस्तानी सेना द्वारा कवर फायर दिए जाने से संबंधित सभी कोशिशों का माकूल जवाब देने के लिए दृढ़ एवं निर्णायक कदम उठाता रहा है.'' स्वराज ने वर्ष 2016 में भारतीय थलसेना की ओर से अंजाम दिए गए सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''वर्ष 2016 में नियंत्रण रेखा पर मौजूद आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध चलाए गए सीमित आतंकवाद-रोधी अभियानों से यह पता चलता है.''

विदेश मंत्री ने कहा, ''अमेरिका सहित कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपने भूक्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति न दे. कई आतंकवादी गुट तथा व्यक्ति, जो पाकिस्तान में शरण लेकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उनका संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों द्वारा बहिष्कार किया गया है.''

उन्होंने कहा, ''वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने जून 2018 में अपने पूर्ण सत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी गुटों, जैसे- लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा तथा फलह-ए-इंसानियत को वित्तपोषण जारी रखने सहित आतंकवादी गुटों को वित्तपोषण जारी रखने संबंधी अपनी चिंताओं के कारण पाकिस्तान को 'ग्रे-लिस्ट' में डाल दिया है.''

इज़राइल में चुनाव से पहले पूर्व सेना प्रमुख ने नए राजनीतिक दल का गठन किया

यरूशलम (एजेंसी)।

इज़राइल के पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैंट्ज ने अप्रैल में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले बृस्पतिवार को अपने नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान किया। माना जा रहा है कि गैंट्ज की पार्टी को चुनाव में कई सीटों पर जीत मिल सकती है। गैंट्ज के नए दल का नाम 'इज़राइल रिजिल्यन्स पार्टी' है। इसका मकसद इजराइल में यहूदी और लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करना बताया जा रहा है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के मुताबिक 2011 से 2015 तक इजराइली सेना के प्रमुख रहे गैंट्ज की पार्टी 120 सदस्यीय नेसेट में 13 से 20 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है।

इससे पहले इज़राइल के सांसदों ने बुधवार को संसद भंग करने ओर नौ अप्रैल को मध्यावधि चुनाव कराने के लिये मतदान किया था। रक्षा मंत्री एविगदोर लीबरमैन के हमास शासित गाजा पट्टी में विवादास्पद संघर्ष विराम समझौते को लेकर नवंबर में इस्तीफा देने के बाद नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास संसद में एक सीट से बहुमत रह गया था। सर्वेक्षणों के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर सत्ता की बागडोर मिल सकती है। हालांकि, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से उनके भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

गैंट्ज से पहले 2013 से 2016 तक नेतन्याहू सरकार में रक्षा मंत्री रहे और पूर्व सेना प्रमुख मोशे यालोन भी बुधवार को अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सदस्य रहे यालोन अब उनके आलोचक और प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं। मीडिया में आ रही खबरों में कयास लगाए जा रहे हैं कि यालोन और गैंट्ज की पार्टियां गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती हैं।

पीयुष पवाईंट पर आटो रिक्शा पलटने से एक बच्चे की मौत कई घायल

सूरत। पांडेसरा के पीयुष पवाईंट के पास शुक्रवार की सुबह 7.30 बजे के करीब एक आटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। जिसमें बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। एक बच्चे के सिर में गंभीर चोट आने से बालक की मौत होने की भी सूचना है। दुर्घटना में घायल बच्चों को सिविल हास्पीटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आस पास के लोग दौड़ आए जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों का कहना है कि रिक्शा के अंदर क्षमता से अधिक बच्चों को भरा गया था, ये बच्चे पांडेसरा के एडम पब्लिक स्कूल के बताए जा रहे है। रिक्शे में सी.के.जी से लेकर पहली क्लास के ही बच्चे थे। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। मृतक बालक के पिता राजु प्रजापति का कहना है कि काल के गाल में समा चुका उनके बच्चे गोरव की उम्र 8 वर्ष थी उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 7 वर्ष है ये दोनों एडम पब्लिक स्कूल में पढते थे। गोरव कक्षा 1 में पढता था तथा दिपक सी.के.जी में पढता है। बच्चों के स्कूल रिक्शा के दुर्घटना ग्रस्त होने की जैसे ही उन्हें जानकारी मिली तो वे तुरंत घटना स्थल पर दौड़ गए वहां घायल सभी विद्यार्थियों को एम्बुलेंस द्वारा सिविल हास्पीटल ले जाया गया। गौरव की मरित्यु से पुरे परिवार में शौक की लहर दौड़ गई। राजस्थान के मुल निवासी राजुभाई प्रजापति सूरत में टाइल्स लगाने का काम करते है। बच्चे की मौत से पुरा पांडेसरा क्षेत्र एक बार फिर शोकाकुल नजर आया। राजभाई का दुसरा पुत्र दीपक जो इस दुर्घटना में घायल हो गया उसने बताय की आटो रिक्षा में कुल पांच विद्यार्थी थे जिसमें पुजा, राहुल गौरव, दीपक सहित एक अन्य विद्यार्थी भी था। रक्शा चालक ने जैसे ही अगला ब्रेक लगाया रिक्शा दुर्घटना ग्रस्त हो गई। घटना की सुचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौक पर पहुंच गई।

सूरत में खेल महाकुंभ 2018 अंतर्गत राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन

राज्य के युवाओं में छुपी सुषुप्त शक्तियों को बाहर लेने के लिए खेल महाकुंभ एक महत्वपूर्ण माध्यम : ईश्वर सिंह पटेल

सूरत। जिला शिक्षा स्तर के विजेता बने 33 जिलों के 1150 पुरुष तथा 22 जिलों के 205 महिला प्रतिभागी खेल महाकुंभ में भाग लेंगे। सूरत खेलकूद युवा एवं संस्कृति विभाग तथा स्पोर्टस अथॉरिटी आफ गुजरात गांधीनगर द्वारा सूरत महानगर पालिका तथा जिला खेलकूद अधिकारी कार्यालय सूरत के सहयोग से खेल महाकुंभ 2018 के राज्य कक्षा स्तर के खेलों का आयोजन किया गया है। 25 से 30 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को राज्य के खेलकूद तथा सहकारिता राज्यमंत्री ईश्वर भाई पटेल ने खेल महाकुंभ में शामिल कुश्ती के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। सूरत के आठवां लाइंस स्थित इंदौर स्टेडियम में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य के जिला कक्षा के विजेता बने 33 जिलों के 1150 पुरुष प्रतिभागियों तथा 22 जिलों के 205 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए तथा स्कूलों कालेजों में युवाओं में खेल के प्रति उत्साह लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार खेल महाकुंभ द्वारा खेलकूद को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष खेल महाकुंभ में 42 लाख प्रतिभागियों के विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा राज्य सरकार राज्य के युवाओं में छुपी शक्तियों को बाहर लाने के लिए खेल महाकुंभ को एक महत्वपूर्ण माध्यम मानती है इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक झंखना बेन पटेल, सुमुल डेयरी के चेयरमैन राजू भाई पाठक उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत अब प्रत्येक गरीब परिवार को मिलेगा गैस कनेक्शन

सूरत। सूरत जिला के 62000 849 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया गरीब महिलाओं को दूल्हे के धोखे से मुक्ति प्रदान करने में यह योजना काफी सहायक सूरत गरीबों महिलाओं वंचितों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत केंद्र सरकार ने कमर कस ली है जिससे वातावरण प्रदूषण मुक्त होकर महिलाओं को चूहे के धोखे से मुक्ति मिली है हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के रोहित शर्मा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार कर लकड़ी कोयला का इस्तेमाल कर भोजन बनाने वाले परिवारों को एलपीजी गैस का कनेक्शन निशुल्क में दिया जा रहा है एससी एचडी पी एम ए वाई कैटेगरी के लोगों को अभी तक 50000000 गैस कनेक्शन दिया जा चुका है इस योजना के तहत स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने अब तक बाकी बचे परिवारों को कनेक्शन प्रदान करने कीड़ा उठाई है सूरत जिला में इस योजना अंतर्गत 62949 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया है।

ड्रींक एण्ड ड्राईव मामले में पुलिस शक्त

सूरत। शहर के डिंडोली क्षेत्र स्थित साई प्वाइंट पर डिंडोली पुलिस द्वारा ड्रींक एण्ड ड्राईव मामले में एक कार चालक तथा उसके साथीयों की जमकर पीटाई की गई। डिंडोली पुलिस का डी.स्टाफ ने गस्त के दौरान एक सफेद रंग की कार को रोका पुलिस को देख कर कार चालक ने भागने की कोशिस की परन्तु भागने में असफल रहा जबपुलिस ने चालक से गाड़ी लेकर भागने की बात पुछी तो उसके मुंह से दारू की दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने जब कार के अंदर बैठे अन्य लोगों को उतारा तो वो भी दारू पीए हुए थे। पुलिस के पुछने पर उन लोगों ने रकछक करते हुए कहा की तुम लोग दारू बेचने वालों को तो पकड़ते नहीं हो तो हमें क्यों पकड़ रहे हो। जिस पर पुलिस कर्मीयों ने कार में बैठे हुए सभी यात्रियों तथा चालक को बुरी तरह पिटने के बाद लोकअप में बंद कर दिया। 31 दिसंबर को लेकर पुलिस पहले से ही एतिहात के तौर पर सर्तकता बरत रही है की कही शराब के नशे में चुर शरारती तत्व शहर में किसी दुर्घटना को अंजाम न देने पाएं। पुलिस की इस शक्ती से दारू पीने वालों में हडकंप मची हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिंडोली स्थित कैलाश नगर सो.सा. निवासी प्रविण पाटील चलथाण से घर आते वक्त डिंडोली साई प्वाईंट के निकट अपनी फोरचुनर कार खड़ी किए थे। उसी समय कार में बैठे तीन लोगों ने बाहर आकर बातचीत करनी शुरु कर दी। जिनके मुंह से दारू की दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उन से जब शराब पीकर कार चलाने की बात की तो उन लोगों ने पुलिस के डी.स्टाफ के साथ गाली गलोच शुरु कर दी जिस पर पुलिस वालों ने उनकी अच्छी तरह पीटाई करने के बाद लाकप में ले जाकर बंद कर दिया और उनके उपर शराब पीकर दारू कार चलाने का मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि घटना के तीन दिन के बाद सी.सी.टी.वी में कैद वीडियों वायरल होने के बाद यह मामला संज्ञान में आया है।

सूरत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस 28 दिसंबर पर शुक्रवार को शहर के विवेकानंद सर्कल स्थित कांग्रेस कार्यालय में 134 वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सूरत शहर तथा जिला के कांग्रेस कार्यकता बड़ीं संख्या में कार्यालय पर उपस्थित रहे।

ट्रैफिक पुलिस के साथ अभद्रता मामले में अल्पेश कथिरिया की धर पकड़

सूरत। ट्रैफिक पुलिस के साथ अभद्रता का व्यवहार करने पर पास कन्वीनर अल्पेश कथिरिया की शुक्रवार को धरपकड़ किए जाने से एक बार शहर का माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रवार की सुबह अल्पेश कथिरिया जैसे ही अपनी कार पार्क कर अपनी दुकान में जा रहे थे उसी समय ट्रैफिक पुलिस ने उनकी कार कार को लॉक कर दिया इस पर ट्रैफिक पुलिस की अल्पेश के साथ कहासुनी हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने अल्पेश कथिरिया से इस मामले में जब पूछताछ की तो अल्पेश ने पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती तथा गाली गलौच करना शुरू कर दिया जिस पर पुलिस ने पकड़ कर वराछा पुलिस स्टेशन में लॉकअप में डाल दिया। लाक्प में होने के बावजूद अल्पेश ने वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी लेकिन पुलिसकर्मियों ने अल्पेश की इस अभद्रता का कोई जवाब नहीं दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पास के बहुत सारे कार्यकर्ता वराछा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी पुलिस ने अल्पेश कथिरिया को ट्रैफिक व्यवस्था में व्यवधान खड़ी करने तथा पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्य का पालन करने में और मानते हुए उन पर कई धाराओं के तहत कोर्ट में पेश किया गया जिस पर कोर्ट में अल्पेश कथिरिया को 15000 के बांड पर जमानत पर रिहा कर दिया इस मामले में पुलिस ने अल्पेश के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी दोषी माना है जिन्न की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है मीडिया से बात करते हुए पुलिस जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)